गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 193
दि. 14.11.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

भारत और बोत्सवाना मिलकर कर सकते हैं न्यायपूर्ण और समावेशी विश्व व्यवस्था का निर्माण : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

(जीएनएस)। गाबोरोन (बोत्सवाना)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को बोत्सवाना की राजधानी गाबोरोन में राष्ट्रीय विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और बोत्सवाना की साझेदारी एक नए युग की शुरुआत कर रही है, जो न्याय, समानता और मानव गरिमा के साझा आदर्शों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की दिशा में कार्य कर सकते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और समावेशी हो।

राष्ट्रपति मुर्मु ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का 'विकसित भारत 2047' विजन और अफ्रीकी महाद्वीप का 'एजेंडा 2063' परस्पर पूरक हैं। दोनों का उद्देश्य मानवीय मूल्यों पर आधारित विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि भारत और बोत्सवाना दोनों ही लोकतंत्र, सुशासन और मानव केंद्रित नीति के आदर्शों को अपनाकर विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ने बोत्सवाना की शासन प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि वहां के नेतृत्व ने देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किया है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के भीतर बोत्सवाना एक ऐसा उदाहरण है जहां सुशासन, पारदर्शिता और विकास के बीच संतुलन कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि

भारत और बोत्सवाना के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत ने बोत्सवाना के मानव संसाधन विकास में अहम भूमिका निभाई है। पिछले दस वर्षों में बोत्सवाना के एक हजार से अधिक छात्रों ने भारत में उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और मानवीय संबंध और गहरे हुए हैं।

राष्ट्रपति मुर्मु ने विशेष रूप से आर्थिक साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि दोनों देश अपने आर्थिक सहयोग की पूरी क्षमता का उपयोग करें। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियां पहले से ही बोत्सवाना के हीरा उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र और अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल नवाचार, औषधि निर्माण, खनन और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की अपार संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि भारत बोत्सवाना के साथ तकनीकी नवाचार और हरित विकास के क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। यह सहयोग दोनों देशों के युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न करेगा और अफ्रीका-भारत संबंधों को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।

अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु ने बोत्सवाना डायमंड ट्रेडिंग कंपनी का निरीक्षण भी किया, जहां उनका स्वागत खनिज और ऊर्जा मंत्री बोगोलो केनेवेंडो तथा विदेश मंत्री फेन्यो बुटाले ने किया। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात कर भारत और बोत्सवाना के बीच हीरा व्यापार और प्रसंस्करण उद्योग में नए आयामों पर चर्चा की।

इसके बाद राष्ट्रपति श्री दिकगोसि स्मारक पहुंचीं, जहां उन्होंने बोत्सवाना के स्वतंत्रता संग्राम के तीन महान जनजातीय नेताओं — खामा तृतीय, सेबेले प्रथम और बाथोएन प्रथम — को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं का संघर्ष न्याय और स्वाधीनता की उस भावना का प्रतीक है जो भारत और बोत्सवाना दोनों के बीच एक गहरी ऐतिहासिक समानता को दर्शाता है।

राष्ट्रपति मुर्मु के इस दौरे को भारत-अफ्रीका संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय सहयोग को नई गति देगी, बल्कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना को भी और सशक्त करेगी, जिससे एक न्यायपूर्ण, समावेशी और संतुलित वैश्विक व्यवस्था की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया जा सकेगा।

दिल्ली धमाका जांच में बड़ा खुलासा, कानपुर के डॉक्टर की गिरफ्तारी से हिल गया नेटवर्क

(जीएनएस)। दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके की जांच ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। विस्फोट के बाद से ही देशभर की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश एटीएस ने बुधवार देर रात कानपुर के हृदयरोग संस्थान में तैनात कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया है। यह गिरफ्तारी न केवल जांच को नई दिशा देती है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि आतंक का यह नेटवर्क मेडिकल पेशे जैसे सम्मानित क्षेत्र तक अपनी जड़ें फैला चुका था।

डॉ. आरिफ मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले हैं और उनकी पहचान एक कुशल चिकित्सक के रूप में थी। तीन महीने पहले ही उन्होंने कानपुर में पदभार संभाला था। लेकिन जांच एजेंसियों के अनुसार, उनके मोबाइल और लैपटॉप से ऐसे कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जो दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी और उसके भाई परवेज से उनकी करीबी की पुष्टि करते हैं। एटीएस ने देर रात उनके अशोकनगर स्थित फ्लैट पर छापा मारा, जहाँ से कई दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। सूत्रों का कहना है कि आरिफ की बातचीत और वित्तीय लेनदेन में कई ऐसे कोडवर्ड मिले हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह किसी बड़े गुट के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहा था। दिल्ली एटीएस की टीम अब उन्हें दिल्ली ले जाकर गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन और परवेज से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि यह पूछताछ कई छिपे राज़ खोलेगी, क्योंकि डॉक्टर आरिफ का नाम हाल के कुछ अन्य संदिग्ध खातों से भी जुड़कर सामने आया है। इस बीच, कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) की कार्रवाई भी तेज हो गई है। श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में गुरुवार को एक साथ 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीआईके की टीमों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर जैश-ए-मुहम्मद से जुड़े कई संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली। जांच

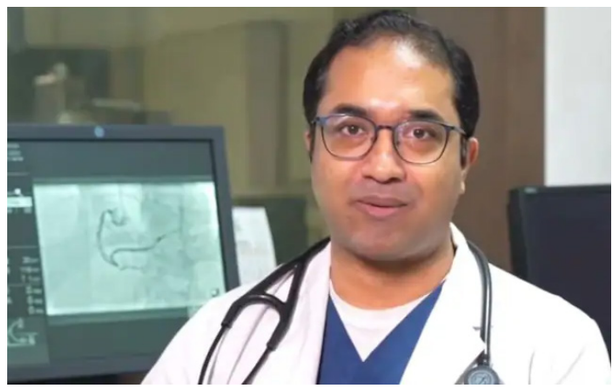

एजेंसियों के अनुसार, इन छापों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि दिल्ली धमाके के सूत्रधारों को वित्तीय या वैचारिक समर्थन कहां से मिल रहा था। कई जगहों से कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, मोबाइल सिम और विदेशी नंबरों से जुड़ी कॉल डिटेल्स बरामद की गई हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में भी सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लाल किला मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों से अगली सूचना तक बंद कर दिया है। यह स्टेशन वायलेट लाइन पर स्थित है और पुरानी दिल्ली के लिए मुख्य संपर्क केंद्र है। इसके बंद होने से पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। सोमवार शाम हुए कार धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार के नंबर और उसमें लगे विस्फोटक उपकरणों के विश्लेषण से पता चला है कि इसे अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया था। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह हमला किसी बड़े नेटवर्क की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसका लक्ष्य दिल्ली जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भय और अस्थिरता फैलाना था।

उधर, असम में इस धमाके के बाद सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भड़काऊ पोस्टों को लेकर भी सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य पुलिस ने पिछले 24 घंटों में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और हिंसा भड़काने के आरोप हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि "राज्य में जो कोई भी हिंसा या आतंकवाद का समर्थन करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया की निगरानी लगातार की जा रही है और किसी को भी नफरत फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" देशभर में इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, यूपी, जम्मू-कश्मीर, असम, बिहार और महाराष्ट्र में प्रमुख सरकारी इमारतों, धार्मिक स्थलों और मॉल्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अब औपचारिक रूप से जांच में शामिल हो रही है और दिल्ली धमाके की जाँच को आतंकवादी साजिश के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली धमाका अब एक स्थानीय घटना नहीं रह गया है, बल्कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की जड़ों को झकझोर दिया है। डॉक्टर से लेकर छात्र तक, हर स्तर पर फैला यह नेटवर्क यह दर्शाता है कि आतंकी संगठन अब समाज के भीतर छिपे हुए चेहरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह जांच न केवल इस साजिश की गहराई उजागर करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि आतंकवाद अब किस तरह नये रूप में अपना ताना-बाना बुन रहा है।

खाद की कालाबाजारी पर लगाम, देश भर में कुल 3,17,054 निरीक्षण और छापे

(जीएनएस)। नई दिल्ली। खरीफ और चालू रबी सीजन 2025-26 के दौरान किसानों तक सुचारू उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। उर्वरक विभाग ने कालाबाजारी, जमाखोरी और मिलावट जैसे मामलों पर नकेल कसते हुए देशभर में कुल 3,17,054 निरीक्षण और छापे मारे। इस दौरान महाराष्ट्र में डायवर्जन-संबंधी उल्लंघनों के लिए 42,566 निरीक्षण किए गए और 1,000 से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए हैं।

केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ने जानकारी दी कि विभाग ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर अप्रैल से नवंबर तक एक व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान राज्य सरकारों के साथ कई संयुक्त बैठकें की गईं। अभियान का

उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखना था। कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए कानूनी उपायों के साथ-साथ प्रभावी कार्रवाई भी की गई।

मंत्रालय के अनुसार, इस सघन कार्रवाई में 5,119 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 3,645 लाइसेंस रद्द या निलंबित किए गए हैं। देशभर में 418 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उत्तर प्रदेश ने इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाई, जहां 28,273 निरीक्षण, 1,957 नोटिस, 157 एफआईआर, और 2,730 लाइसेंस रद्द/निलंबित किए गए। वहीं, महाराष्ट्र ने भी बड़े पैमाने पर निरीक्षण दलों की तैनाती कर त्वरित कानूनी कार्रवाई की है।

कलकत्ता हाईकोर्ट मुकुल राय की विधायकी गई

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कृष्णनगर उत्तर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक मुकुल राय की सदस्यता रद्द कर दी। न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और शब्बर राशिदी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मुकुल राय के तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने से उन्होंने दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है।

गौरतलब है कि मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और उन्हें पार्टी का 'रणनीतिक चाणक्य' कहा जाता था। 2017 में भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने 2021 में जीत दर्ज की थी, मगर दोबारा टीएमसी में लौटने के बाद अब उनकी विधायकी पर अंतिम मुहर न्यायपालिका ने लगा दी है।

मुकुल राय ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन एक वर्ष बाद यानी 2022 में उन्होंने दोबारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का दामन थाम लिया। इसी कदम को लेकर उनकी सदस्यता पर सवाल उठे और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष से दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने उस समय मुकुल राय की सदस्यता बरकरार रखी थी, जिसके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अब अदालत ने अध्यक्ष के फैसले को पलटते हुए साफ कहा कि राय ने संविधान के अनुच्छेद 10 के तहत लागू नियमों का उल्लंघन किया है और इसलिए उनकी सदस्यता अमान्य घोषित की जाती है।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा—"यह फैसला न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि भारत के संवैधानिक इतिहास में भी ऐतिहासिक है। न्याय ने अंततः जीत हासिल की।" राजनीतिक हलकों में इसे तृणमूल कांग्रेस के लिए एक प्रतीकात्मक झटका और भाजपा के लिए नैतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है।

भारत साझा करेगा सुशासन और स्मार्ट सिटी विकास का अनुभवः डॉ. जितेंद्र

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत अब मालदीव के अधिकारियों को सुशासन, स्मार्ट सिटी विकास और प्रशासनिक सुधारों के अपने अनुभव से प्रशिक्षित करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत सार्वजनिक नीति, नीली अर्थव्यवस्था, महासागरीय तकनीक, स्टार्टअप नीति और बुनियादी ढांचा विकास जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता मालदीव के साथ साझा करने को पूरी तरह तैयार है। डॉ. सिंह ने यह बात राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NGC) में मालदीव के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान कही। यह प्रतिनिधिमंडल मालदीव के नगर, स्थानीय सरकार और सार्वजनिक कार्य मंत्रालय के राज्यमंत्री अहमद सलीम के नेतृत्व में भारत आया है। दल 3 से 14 नवंबर तक मसूरी स्थित केंद्र में चल रहे "स्मार्ट सिटी मिशन" पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की सशक्त सिविल सेवा प्रणाली विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक संस्थानों के बीच समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे शासन व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। उन्होंने मालदीव के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों जैसे भारत के प्रमुख विकास मॉडल से प्रेरणा लें।

डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की यह पहल केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच ज्ञान और विश्वास पर आधारित साझेदारी को और मजबूत करेगी।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक सुरेन्द्र कुमार बगड़े ने बताया कि केंद्र कई देशों, विशेषकर मालदीव, के अधिकारियों के लिए क्षेत्रवार विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि वे अपने-अपने देशों में विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर सकें।

लाल किला विस्फोट पर तुर्किये का सख्त जवाब, भारत में साजिश में शामिल होने के आरोपों को बताया मनगढ़ंत

(जीएनएस)। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए भयावह विस्फोट के बाद जब जांच एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की संभावना जताई, तो बुधवार देर रात तुर्किये सरकार ने एक औपचारिक बयान जारी कर इस पूरे विवाद पर अपनी स्थिति साफ की। अंकारा ने भारत के कुछ मीडिया संगठनों द्वारा लगाए गए आरोपों को "दुर्भावनापूर्ण, झूठे और पूरी तरह से निराधार" बताते हुए कहा कि तुर्किये का इस हमले से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है और ऐसी बातें दोनों देशों के संबंधों को कमजोर करने की सुनियोजित कोशिश हैं।

तुर्किये के संचार निदेशालय की ओर से जारी विस्तृत बयान में कहा गया है कि "तुर्किये एक ऐसा राष्ट्र है जिसने हमेशा आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति का कड़ा विरोध किया है। हमारा देश न केवल संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति का सक्रिय सदस्य है, बल्कि नाटो के ढांचे में भी आतंकवाद विरोधी अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाता है। ऐसे में यह आरोप कि तुर्किये किसी देश को आतंकवादी संगठनों को समर्थन दे रहा है, न केवल असत्य हैं बल्कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र को धूमिल करने का प्रयास हैं।"

बयान में यह भी कहा गया कि तुर्किये किसी

भी परिस्थिति में किसी देश के खिलाफ कट्टरपंथी या हिंसक गतिविधियों का समर्थन नहीं करता। अंकारा ने भारतीय मीडिया से अपील की है कि वह बिना प्रमाण वाले दावों को प्रचारित न करे और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करे। तुर्किये सरकार ने यह भी कहा कि "ऐसी खबरें अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना को चोट पहुँचाती हैं, खासकर तब जब पूरी दुनिया आतंकवाद जैसे वैश्विक खतरे से एकजुट होकर लड़ रही है।"

हालांकि, भारत की जांच एजेंसियां इस समय दिल्ली धमाके की जांच को केवल घरेलू सीमा तक सीमित नहीं रख रही हैं। शुरुआती जांच में कुछ ऐसे डिजिटल साक्ष्य और यात्राओं के रिकॉर्ड सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ आरोपियों ने पिछले वर्ष तुर्किये का दौरा किया था। वहीं, खुफिया रिपोर्टों में इस बात के संकेत मिले हैं कि तुर्किये की भूमि पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद से जुड़े व्यक्तियों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। यही नहीं, एक आरोपी के फोन से प्राप्त डेटा में इस्तांबुल और अंकारा से किए गए कुछ एन्क्रिप्टेड कॉल्स का विवरण भी मिला है, जिनकी जांच अब अंतरराष्ट्रीय सहयोग से की जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स इस संभावना की पड़ताल कर रही हैं कि क्या तुर्किये की यात्रा के दौरान ही इस हमले की योजना बनाई गई थी। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, "हम किसी देश को दोषी नहीं ठहरा रहे, पर यह सत्य है कि कुछ आरोपियों ने वहां रहकर संदिग्ध संपर्कों से मुलाकात की। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उन बैठकों में क्या तय हुआ और क्या वही दिल्ली विस्फोट की नींव बनी।" भारत सरकार ने इस घटनाक्रम पर अभी तक कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी देश पर सीधे आरोप लगाना जल्दबाजी होगी।

संपादकीय

धमाके के सुलगते सवाल

सुरक्षा की दृष्टि से चाकचौबंद मानी जाने वाली देश की राजधानी में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके ने कई ज्वलंत सवालों को जन्म दिया है। सुरक्षा व्यवस्था के छिद्रों को पाटने की जरूरत के साथ चेताया है कि हमारी जरा सी चूक से आतंकवादियों को फिर से पांव जमाने का मौका मिल सकता है। अब जब मामले की जांच देश की शीर्ष खुफिया एजेंसियां कर रही हैं तो जांच के निष्कर्ष ही हकीकत बताएंगे। लेकिन धमाके का स्तर और उससे हुई जनधन की हानि चिंता बढ़ाने वाली है। निश्चित ही यह घटना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। सवाल यह भी उठता है कि चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपराधी कैसे इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ संवेदनशील इलाके में ले जाने में सफल हुए। प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार जम्मू-कश्मीर के रास्ते उत्तर प्रदेश व हरियाणा तक फैले कश्मीरी डॉक्टरों के एक समूह ने घटना को अंजाम दिया। इस घटनाक्रम ने पूरे देश को चौंकाया कि समाज में दूसरे भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टर कैसे लोगों के चिथड़े उड़ाने वाले कृत्य को अंजाम दे सकते हैं? उनकी उस शपथ का क्या हुआ जो डॉक्टर पढ़ाई पूरी करने के बाद लोगों की जीवन रक्षा के लिए लेते हैं? अब तक यह मान्यता रही है कि आतंकवादी संगठनों से वे लोग ही जुड़ते हैं, जो कम पढ़े-लिखे होते हैं और विध्वंसकारी ताकतों के बहकावे में आकर आतंकवाद की राह में उतर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इस आतंक के स्लीपर सैल में डॉक्टरों के समूह का शामिल होना बेहद चिंता का विषय है। जो समाज के उस विश्वास को तोड़ता है कि डॉक्टर हमेशा जीवन देने वाला ही होता है। भविष्य में यह खतरनाक प्रवृत्ति अन्य व्हाइट क़ॉलर जॉब करने वाले समूह को भी घातक रास्ते पर ले जा सकती है। ऐसे में हमें लाल किले के निकट घटी घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और आसन्न खतरे को महसूस भी करना चाहिए। बहरहाल, लाल किले के निकट की घटना एक आतंकी साजिश थी या बड़ी साजिश को अंजाम देने निकले अपराधियों की चूक से समय से पहले घटी घटना, ये एनआईए की जांच से ही पता चल सकेगा। लेकिन जो क्षति घटनास्थल पर हुई है वह किसी आतंकी घटना से कम तो नहीं है। बहरहाल, राष्ट्रीय राजधानी में हुई घटना के चलते भविष्य के खतरे के मद्देनजर सभी दृष्टिकोणों से मामले की जांच की जानी चाहिए। शायद इसी कारण से दिल्ली पुलिस ने यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम व अन्य कठोर धाराओं में मामला दर्ज करके जांच का दायरा बढ़ाया गया है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के प्रश्न भी हमारे सामने हैं कि कैसे अपराधी इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ राजधानी में ले जाने में सफल हुए। जिसके चलते भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। याद रहे कि अतीत में भी कई बार दिल्ली को आतंक से दहलाने की कोशिशें हुई हैं। हमें उन घटनाओं से भी सबक लेने की जरूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद के मामले में जरा सी चूक भी व्यापक क्षति का सबब बन सकती है। देश को अस्थिर करने की किसी भी साजिश को विफल बनाने और आम लोगों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिये सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस नये टेरर मॉड्यूल के मद्देनजर भी निगरानी का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। पता लगाने की जरूरत है कि कैसे अपराधी इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ वाया फरीदाबाद दिल्ली पहुंचाने में सक्षम बने। वैसे हाल के वर्षों में देश के भीतर आतंकी घटनाओं पर लगभग विराम लगा हुआ था, लेकिन हालिया घटना ने हमारी चिंताओं को बढ़ाया ही है। हमें आतंकवाद को बढ़ावा देने के हर प्रयास को सख्ती से कुचलने की जरूरत है। सजग और सतर्क खुफिया तंत्र इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकता है। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि इस कांड में सीमा पार सक्रिय आतंकी संगठनों की भूमिका तो नहीं है। बिना बाहरी मदद के इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना सहज नहीं हो सकता। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का पनपना हमारी गहरी चिंता का विषय भी होना चाहिए।

बिहार चुनाव परिणाम आकलन

क्या धुंध के पीछे छुपा सूर्य आज से नई सुबह की आगाज़ करेगा?

> अगर वो सूरज समय-से पहले परिणाम के रुझान निकालने लगे तो शायद सत्ता की छांव जल्दी छँटेगी; और यदि धुंध ने ताल ठोक दी, तो इंतज़ार लम्बा खिंच सकता है।

कुश मेहता
(स्वतंत्र पत्रकार)
साबरमती तट,
अहमदाबाद
(गुजरात)

रात भर छाए अनुमान, दावों और दलीलों की धुंध अब धीरे-धीरे हटने लगी है। बिहार की सुबह कुछ अलग है—सड़कें शांत हैं, हवा में हल्की नमी है, और हर चेहरे पर एक अनकहा इंतज़ार। कोई अपने हिसाब से परिणाम लिख चुका है, कोई अभी भी गणित जोड़ रहा है, लेकिन आज का सवेरा तय करेगा कि जनमत की रोशनी किसके माथे चमकेगी और किसके चेहरे की धुंध और गहरी हो जाएगी।

सुबह के पहले उजाले के साथ ही ईवीएम की खामोशी टूटेगी, और उसी क्षण से शुरू होगा सच्चाई का उजाला—वही उजाला जो बताएगा कि सत्ता की धूप किसे मिलेगी और किनके सपने कोहरा बनकर उड़ जाएँगे। बिहार का नया सवेरा अब बस कुछ कदम दूर है, बस धुंध पूरी तरह छँटने की देर है।

आज जब परिणाम की घड़ी करीब आ रही है, तो उस सूर्य की किरणें राजनीति की धुंध को चीरने को तैयार हैं। सहमे चेहरे, गूंगी घोषणाएं, उभरी उम्मीदें — सब एक-एक करके खुले मैदान में उतरने वाले हैं। इस नए सवेरे में पता चलेगा कि किसके हाथ में सत्ता की जमीं होगी, और किसके मार्ग पर ही धुंध फिर लौटेगी। वोटर की उमड़ी लहर, गठबंधनों की उलझन, पुराने अनुभव की खामोशी — सब मिलकर इस सुबह को विशेष बना रहे हैं। अगर वो सूरज समय-से पहले परिणाम के रुझान निकालने लगे तो शायद सत्ता की छांव जल्दी छँटेगी; और यदि धुंध ने ताल ठोक दी, तो इंतज़ार लम्बा खिंच सकता है।

Axis My India के अनुसार, (एनडीए) को लगभग 121-141 सीटें मिल सकती हैं।

वहीं दूसरी ओर, महागठबंधन को को लगभग 98-118 सीटें मिलने का अनुमान है।

एक अन्य पोलस्टर, Today's Chanakya, एनडीए को 160 12 सीटें तक का विजयी आंकलन दे रहा है, जबकि महागठबंधन को लगभग 77 12 सीटें।

अधिकांश समाचार समीक्षाएं एन डी ए को स्पष्ट बहुमत का संकेत दे रहे है किंतु इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़

मतदान ऊंट किस करवट बैठेगा उसकी कवायद की कथा भी लिखने को आतुर है अब यह कथा यथावत जारी रखेगी या कांटे की टक्कर से किसी और का भविष्य बनाएगी यह आज दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा ,

परन्तु यह भी सत्य साबित होगा कि कई परिणाम चौंकाने वाले हो सकते है जन सुराज पार्टी अपने टारगेट से दो अंकों में पहुंच कर अनेक लोगों का समीकरण बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

धुंध अभी पूरी तरह नहीं छँटी। ये अनुमान बताएँगे कि किसके फूल खिले हैं और किसके पंख उड़ान भरने से पहले कतर रहे हैं। और जैसे-जैसे परिणाम सामने आएँगे, वही तय करेगा कि बिहार की सुबह कौन जागते चेहरे लेकर आएगी — सत्ताधारी गठबंधन का आत्मविश्वास, या विरोधियों का नया जोश।

प्रमुख सर्वे-एजेंसियों द्वारा 2025 बिहार चुनाव के पूर्वार्ध और एग्जिट-पॉल के एजेंसी-वार अनुमान दिए जा रहे हैं

एजेंसी का नाम अनुमानित सीट एनडीए एवं महागठबंधन

Axis My India 121-141 सीटें 98-118 सीटें

अपेक्षाकृत संकुचित रेंज, मुकाबला करीब दिखा रहा है

IANS Matrize 147-167 सीटें 70-90 सीटें

एनडीए को बहुत बड़ा अनुमान

People's Insight 133-148 सीटें 87-102 सीटें

Chanakya Strategies 130-138 सीटें 100-108 सीटें मुकाबला बहुत करीब दिखा रहा है

Dainik Bhaskar 145-160 सीटें 73-91 सीटें

एनडीए को बहुत ऊँचा अनुमान

अन्य-एजेंसियाँ (जैसे JVC Poll, P Marq, TIF Research) ₹135-162 सीटें एनडीए को स्पष्ट बहुमत का अनुमान

प्रमुख निष्कर्ष

अधिकांश सर्वे-एजेंसियों ने एनडीए को बहुमत से ऊपर सीटें मिलने का अनुमान दिया है।

लेकिन रेंज काफी भिन्न-भिन्न है — कुछ एजेंसियाँ बहुत उच्च (145-160+) सीटें दे रही हैं, तो कुछ अपेक्षाकृत 'नज़दीकी मुकाबला' (121-141) का अनुमान दे रही हैं।

मतलबः वोट शेयर में मुकाबला बेहद करीब दिख रहा है, लेकिन सीटों में एनडीए को लाभ का संकेत मिलने लगा है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि नए दल/गुट जन सुराज पार्टी को अधिकांश अनुमान में बहुत कम सीटें दिख रही हैं। किंतु उम्मीद है की यह भी समीकरणों को बहुत प्रभावित करेगा ।

प्रेरणा

सच्ची विजय का अर्थ

दुनिया के इतिहास में सिकंदर महान का नाम अमर है। वह वह राजा था जिसने कम उम्र में ही असीम शक्ति और अद्वितीय पराक्रम से अनगिनत देशों को जीत लिया। उसकी तलवार के आगे साम्राज्य झुक गए, उसकी सेना के आगे बड़े-बड़े योद्धा हार मान गए। किंतु मनुष्य की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती — सिकंदर भी अपवाद नहीं था। वह स्वयं को संसार का स्वामी मानने लगा था, एक ऐसा विजेता जो सब कुछ जीत सकता है। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी वृद्धा ने ऐसा सत्य दिखाया कि उसका हृदय बदल गया, और उसे समझ आया कि असली विजय तलवार से नहीं, विनम्रता और सत्य से होती है।

एक बार सिकंदर अपने सैनिकों के साथ एक छोटे से नगर को चारों ओर से घेर चुका था। नगर की गलियों में भय का सन्नाटा पसरा था, घरों के दरवाजे बंद थे, और हवा में तनाव घुला हुआ था। युद्ध की तैयारी पूरी थी, परंतु दिनभर की थकान और लंबी यात्राओं के बाद सिकंदर स्वयं भूख से व्याकुल था। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वह कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता है और नगर के भीतर भोजन की तलाश में निकल पड़ा।

शाम का समय था, सूर्य अस्त हो चुका था, आकाश में लालिमा फैल रही थी। उसी समय वह एक छोटे से कच्चे मकान के सामने जाकर रुका। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर आवाज़ आई, "कौन है?" सिकंदर ने कहा, "एक राहगीर हूं, भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा?" दरवाजा खुला, और सामने एक वृद्धा खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्र का अनुभव और चेहरे पर मातृत्व की करुणा झलक रही थी। उसने सैनिक वेश में खड़े उस व्यक्ति को देखा और तुरंत पहचान लिया — वह कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि स्वयं सिकंदर था।

फिर भी, बिना किसी भय के उसने मुस्कराकर कहा, "आओ बेटा, थके लगते हो। तुम मेरे घर आए हो, यह मेरा सौभाग्य है।" सिकंदर ने सिर झुकाया और कहा, "मां, बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो आशीर्वाद होगा।" बुढ़िया बिना कुछ बोले भीतर चली गई। कुछ देर बाद वह एक थाली लेकर लौटी, जो कपड़े से ढकी हुई थी। सिकंदर के चेहरे पर संतोष की झलक आई — उसे लगा अब रोटियां सामने होंगी। लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, तो उसकी आंखें फैल गईं। थाली में रोटियां नहीं, बल्कि सोने-चांदी के चमकते गहने रखे थे।

सिकंदर ने विस्मय से पूछा, "मां, मैंने तो खाना मांगा था, ये गहने क्यों दिए?" बुढ़िया ने शांत स्वर में कहा, "बेटा, मुझे लगा तुम्हारी भूख रोटियों की नहीं, सोने-चांदी की है। अगर तुम्हारी भूख रोटियों की होती, तो तुम अपने देश से निकलकर दूसरे देशों को लूटने क्यों आते? तुम तो हर जगह संपत्ति, राजसिंहासन और सत्ता की तलाश में जाते हो। इसलिए मैंने सोचा, यही तुम्हारा भोजन होगा।"

बुढ़िया के ये शब्द सुनकर सिकंदर का चेहरा कठोरता से दया और लज्जा में बदल गया। वह कुछ देर मौन खड़ा रहा, फिर उसके चेहरे पर गहरी सोच उतर आई। जीवन में पहली बार किसी ने उसकी विजय की भूख पर प्रश्नचिह्न लगाया था। उसके भीतर से आवाज आई — "क्या सचमुच मैं भूखा हूं? क्या यह भूख रोटी की है या अहंकार की?"

सिकंदर धीरे से बुढ़िया के चरणों में झुक गया और कहा, "मां, तूने मेरी आंखें खोल दीं। मैंने अनेक देशों को जीता, पर स्वयं को नहीं जीत सका। आज पहली बार मुझे अपनी हार का एहसास हुआ है।"

बुढ़िया ने स्नेह से उसका सिर उठाया, उसकी आंखों में झांका और कहा, "बेटा, सच्चा विजेता वह नहीं जो तलवार से देशों को जीत ले, बल्कि वह है जो अपने भीतर के लोभ, अहंकार और क्रोध को जीत ले। धन और साम्राज्य क्षणिक हैं, पर सत्य और करुणा अमर हैं।"

इन शब्दों ने सिकंदर के मन को झकझोर दिया। वह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, "मां, अब मैं समझ गया हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी विजय अपने मन पर विजय पाना है।" बुढ़िया ने उसे प्रेमपूर्वक भोजन कराया। सिकंदर ने वह रोटियां इस श्रद्धा से खाईं जैसे वह कोई प्रसाद हों।

अगले दिन जब उसने अपनी सेना के सामने आकर आदेश दिया कि नगर पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, तो उसके सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, "महाराज, यह कैसा निर्णय है? इतनी मेहनत के बाद अब क्यों लौटना?"

सिकंदर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, "उस नगर में एक मां रहती है जिसने मुझे सिखाया कि तलवार से नहीं, सच्चाई से जीत हासिल होती है। उस भूमि को जीतने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां आत्मा की शक्ति है।"

सिकंदर ने उस नगर को छोड़ा और अपने अभियान से लौट गया। उस दिन के बाद उसके भीतर का दृष्टिकोण बदल गया। वह अब केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि आत्मिक शांति की खोज में लग गया। उसके हृदय में उस बुढ़िया के शब्द अमिट हो गए — "सच्ची विजय भीतर होती है, बाहर नहीं।"

समय बीत गया, साम्राज्य मिट गए, किंतु वह कहानी आज भी जीवित है। वह यह सिखाती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के लालच, अहंकार और हिंसा को नहीं हराता, तब तक वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चा विजेता नहीं बन सकता। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वही वास्तव में विश्वविजेता है — वही सच्चे अर्थों में "महान" कहलाने के योग्य है।

शीघ्र लागू की जाएं चारों श्रम संहिताएं, संतुलित विकास का ढांचा प्रदान करने में सक्षम होंगी

भारत के कार्यबल को ऐसे औपचारिक रोजगार में तेजी से जगह मिलनी चाहिए, जहां उचित वेतन और व्यापक सामाजिक सुरक्षा मिले, जिससे विकास के लाभ से सभी को सुरक्षित और सम्मानजनक आजीविका प्राप्त हो। पुराने श्रम नियमों के बने रहने से गुणवत्तापूर्ण रोजगार देने की उद्यमों की क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित हुई। इसी के आलोक में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रम सुधारों की जो कल्पना की, वह काफी समय से लंबित थी। इन्हें 2019 और 2020 के बीच संसद द्वारा चार श्रम संहिताओं के रूप में पारित किया गया।

ये संहिताएं देश के श्रम परिदृश्य को आधुनिक बनाने और संरचनात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती हैं। दशकों पुराने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाते हुए चार नई श्रम संहिताओं के निर्माण का उद्देश्य न केवल कानूनों को एकीकृत स्वरूप प्रदान करना है, बल्कि काम को अधिक निष्पक्ष, सुरक्षित और उत्पादक बनाना है। मजदूरी संहिता, 2019 यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है कि प्रत्येक श्रमिक को श्रम की गरिमा का सम्मान करने वाला न्यूनतम वेतन मिले। पहले न्यूनतम वेतन केवल निर्धारित व्यवसायों तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे सभी क्षेत्रों और संगठित और असंगठित के समस्त श्रमिकों पर लागू कर दिया गया है। यह न्यूनतम वेतन का सार्वभौमीकरण श्रमिकों को कानूनी रूप से बुनियादी वेतन का अधिकार देता है। इसके साथ ही पहली बार एक राष्ट्रीय आधार वेतन (फ्लोर वेज) की व्यवस्था की गई है, जिसे केंद्र सरकार जीवन स्तर और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय करेगी। कोई भी राज्य इससे कम न्यूनतम वेतन नहीं तय कर सकेगा। इससे राज्यों के बीच वेतन असमानता भी घटेगी और देशभर के श्रमिकों को समान अवसर मिलेगा। संहिता यह भी सुनिश्चित करती है कि वेतन की समीक्षा नियमित रूप से हो, ताकि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप श्रमिकों की आय प्रासंगिक बनी रहे। इस संहिता के तहत विवादों में प्रमाण प्रस्तुत करने का भार नियोक्ता पर होगा, जिससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 स्वतंत्र भारत में जन कल्याण के सबसे समावेशी विस्तारों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम सहित नौ प्रमुख कानूनों को मिला कर यह एक एकीकृत प्रणाली स्थापित करती है, जो पारंपरिक और नए, दोनों प्रकार के कार्यों को कवर करती है। पहली बार गिग श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राष्ट्रीय कार्यबल का हिस्सा माना गया है। प्रत्येक श्रमिक को पंजीकृत किया जाएगा, उसे एक विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा संख्या जारी की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और मातृत्व सहायता जैसे लाभ का सीधा वितरण संभव हो सकेगा।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 राष्ट्र का निर्माण करने वालों के प्रति देखभाल और जिम्मेदारी का एक संदेश है। प्रतिष्ठान की परिभाषा को व्यापक बनाकर यह संहिता उन लाखों लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, जो पहले सुरक्षा कानूनों के दायरे में नहीं आते थे। प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी का विवरण, पदनाम, श्रेणी, वेतन का ब्यौरा तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विवरण सम्मिलित होंगे। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य करती है और नियोक्ताओं से अपेक्षा करती है कि वे इस मद में कर्मचारियों पर कोई वित्तीय बोझ न डालें और सुरक्षित एवं स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखें। यह संहिता लैंगिक समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति करती है। यह महिला श्रमिकों को सभी प्रतिष्ठानों और रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देती है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 तीन पुराने अधिनियमों को एकीकृत ढांचे में मिला करके नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों में स्पष्टता लाती है। इसमें बीस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को शिकायत निवारण समितियां गठित करने का प्रविधान है, ताकि विवादों का शीघ्रता से समाधान हो जाए तथा हड़ताल या मुकदमेबाजी की स्थिति न बने। इस संहिता के तहत छंटनी का सामना कर रहे श्रमिक अब 30 दिन का नोटिस और पर्याप्त मुआवजा पाने के हकदार हैं। यह एक मानवीय सुधार है, जो आजीविका सुरक्षा का सम्मान करता है।

विभिन्न विकासशील देशों के उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि श्रम सुधारों ने उनकी आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थिति, बढ़ते टैरिफ तथा व्यापार ढांचों में बदलाव को देखते हुए भारत में नई श्रम संहिताओं को जल्द से जल्द लागू करना अत्यंत आवश्यक है। श्रम नियम सरल एवं पारदर्शी होने पर निवेश बढ़ेगा, औपचारिक रोजगार बढ़ेगा तथा श्रमिकों के गरिमापूर्ण अधिकार सुनिश्चित होंगे।

स्वचालन और डिजिटलीकरण के युग में जब पारंपरिक नौकरियां घट रही हैं, तब ये संहिताएं संतुलित विकास का ढांचा प्रदान करने में सक्षम होंगी। चारों श्रम संहिताएं उस महत्वाकांक्षा की रीढ़ हैं, जिसमें आर्थिक गतिशीलता को सामाजिक न्याय के साथ जोड़कर एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की कल्पना की गई है।

अभियान

जब देवर्षि नारद को मिला अहंकार का श्राप — कामदेव पर विजय के बाद भी हार गए मुनि अपने ही 'मैं' से

देवताओं के बीच देवर्षि नारद एक अद्वितीय स्थान रखते थे। वे ब्रह्मा के मानसपुत्र, विष्णु के परम भक्त और लोककल्याण के अग्रदूत थे। उनके वीणा के तारों से जब "नारायण-नारायण" की ध्वनि गूंजती, तो दिशाएँ पवित्र हो उठतीं। किंतु यही नारद एक समय अपने ही अहंकार में उलझ गए — और यही उनका पतन का कारण बना। यह कथा हमें सिखाती है कि जब साधक अपने तप, ज्ञान या शक्ति पर गर्व करने लगता है, तब वही गर्व उसकी सारी साधना को भस्म कर देता है।

एक बार नारद मुनि गहन तप में लीन थे। उनका ध्यान इतना प्रगाढ़ था कि संसार के कोई भी विकार उन्हें छू नहीं पा रहे थे। तभी कामदेव, जो देवताओं में मनोवेग जगाने वाला सबसे शक्तिशाली देवता है, उन्हें विचलित करने आया। उसने अपने पुष्प बाण चलाए, वातावरण को सुगंध और मधुरता से भर दिया, वसंत का मादक झोंका चारों ओर फैल गया। किंतु नारद का मन अडिग रहा — वे जैसे किसी और लोक में थे। कामदेव की सारी शक्ति उस तपस्वी के तेज के सामने निष्फल हो गई।

कामदेव ने लज्जित होकर देवराज इंद्र के दरबार में जाकर सब कुछ बताया। देवसभा में आश्चर्य छा गया। तुलसीदास जी ने भी इसी प्रसंग को अत्यंत सुंदर शब्दों में वर्णित किया —

"मुनि सुसीलता आपनि करनी।
सुरपति सभाँ जाइ सब बरनी।।
सुनि सब कें मन अचरजु आवा।
मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा।।"

अर्थात जब कामदेव ने नारद की महिमा का बखान किया, तब सब देवता चमत्कृत हो गए। वे जानते थे कि ऐसी विजय केवल प्रभु की कृपा से ही संभव है, इसलिए उन्होंने नारद की प्रशंसा करते हुए सिर श्रीहरि विष्णु के चरणों में झुका दिया।

इधर नारद मुनि के मन में संतोष के साथ एक सूक्ष्म गर्व का भाव जन्म लेने लगा। उन्होंने सोचा — "मैंने इतना महान कार्य किया है, पर इसकी गवाही कौन देगा? कौन कहेगा कि नारद ने कामदेव को जीत लिया?" वे मन ही मन सोचने लगे कि यदि वे यह कथा भगवान शंकर को सुनाएँगे, तो उन्हें सबसे सच्ची प्रशंसा मिलेगी। क्योंकि कामदेव को पहले भगवान शंकर ने भी भस्म किया था।

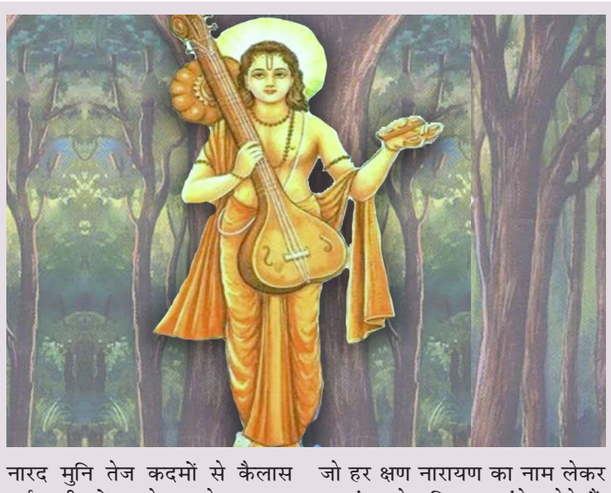

नारद मुनि तेज कदमों से कैलास पर्वत की ओर चले। उनके मुख पर गर्व की मुस्कान थी। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और बोले — "महादेव! आज मैंने भी कामदेव को जीत लिया। मेरे तप के आगे उसके बाण निष्फल हो गए। वह भाग खड़ा हुआ।"

शिव मुस्कुराए, किंतु मौन रहे। उन्होंने मुनि की बात पूरी सुनी। वे जानते थे कि आज नारद का स्वर साधक का नहीं, विजेता का है। वे सोचने लगे — "आज वही मुनि, जो हर क्षण नारायण का नाम लेकर ब्रह्मांड को भक्ति का संदेश देते हैं, उनके मुख से आज अहंकार की गंध आ रही है। यह कथा जैसे अमृत नहीं, विष के समान है। मैंने जब कालकूट विष पिया था, तब भी इतना क्लेश नहीं हुआ जितना इस आत्मगौरव भरी बात को सुनकर हो रहा है।"

फिर भी भगवान शंकर ने नारद को कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि किसी साधक के भीतर जब अहंकार का बीज अंकुरित होता है, तो उसे रोकने का नहीं, समझाने का समय होता है। उन्होंने मृदु स्वर में कहा — "देवर्षि, आपने असंभव को संभव कर दिखाया। पर मेरी एक विनती है — इस घटना का वर्णन भूलकर भी भगवान विष्णु के समक्ष मत करना। ऐसा करने से अहंकार बढ़ेगा और वह आपकी साधना के मार्ग में बाधा बनेगा।"

नारद मुनि ने मुस्कराकर सिर हिलाया, पर मन में विचार आया — "शिवजी तो ईर्ष्यालु हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि अब कामदेव पर विजय की महिमा केवल उन्हीं की नहीं रही।" वे यह नहीं समझ पाए कि शंकर की सलाह उनके कल्याण के लिए थी, न कि किसी प्रतिस्पर्धा के लिए।

कुछ समय बाद, विष्णु लोक में पहुँचकर मुनि ने वही कथा गर्व से सुनाई। वे बोले — "प्रभु, आपके भक्त ने कामदेव जैसे देवता को पराजित किया!" भगवान विष्णु मुस्कराते रहे। उन्हें पता था कि अब अहंकार ने मुनि के मन पर अधिकार कर लिया है। और यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड के श्रेष्ठ तपस्वी नारद को अपने ही 'मैं' से पराजित होना था। यह कथा यहाँ समाप्त नहीं होती — बल्कि यही आरंभ है उस प्रसंग का जब विष्णु माया के प्रभाव से नारद का मोहभंग हुआ और उन्हें श्राप मिला। पर उस अगले अध्याय से पहले इस प्रसंग का गूढ़ अर्थ यही है कि कामदेव शरीर की इंद्रियों को हरा सकता है, पर अहंकार आत्मा को। और जब आत्मा ही मोहित हो जाए, तो साधना का अर्थ समाप्त हो जाता है। नारद का यह प्रसंग मानव जीवन का दर्पण है। जब हम किसी विजय, ज्ञान, पद या प्रसिद्धि को "मेरे प्रयास" का परिणाम मान लेते हैं, तब हम उसी सूक्ष्म भूल को दोहराते हैं जो देवर्षि नारद से हुई थी। सफलता का अर्थ यह नहीं कि हम बड़े हो गए, बल्कि यह कि ईश्वर ने हमें अपने माध्यम के रूप में चुन लिया। इसलिए जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह कुछ नहीं करता, सब प्रभु करते हैं — वही सच्चे अर्थों में विजेता है। क्योंकि अहंकार में जीता व्यक्ति संसार को जीतकर भी स्वयं से हार जाता है, जबकि नम्र व्यक्ति संसार से हारकर भी ईश्वर को पा लेता है। यही नारद की कथा का अनन्त संदेश है — "सच्ची विजय वही है जिसमें 'मैं' का भाव मिट जाए और केवल 'तू' रह जाए।"

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

श्वेत क्रांति से राष्ट्र क्रांति की ओर प्रयाण

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह :-

- भारत की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और इस लड़ाई में वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री का नाम शीर्ष पर
- सहकारी क्षेत्र के अग्रणियों की मेहनत से आज देश और राज्य के किसानों, पशुपालकों और गांवों के लिए समृद्धि के द्वार खुले हैं

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रबल राष्ट्रभावना उत्तर गुजरात का स्वभाव रहा है
- सैनिक स्कूल 'राष्ट्रहित सर्वोपरि' के ध्येय के साथ भावी पीढ़ी के निर्माण का माध्यम बनेगा

मुख्यमंत्री के करकमलों से राष्ट्रीय भावना, साहस, अनुशासन और मां भारती के लिए समर्पित श्री मोतीभाई आर चौधरी सैनिक स्कूल का लोकार्पण

30 मीट्रिक टन दैनिक प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग की क्षमता वाले खेरालू सागर ऑर्गेनिक प्लांट का ई-लोकार्पण

(जीएनएस)। गांधीनगर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की वर्चुअल उपस्थिति तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में गुरुवार को मेहसाणा जिले के बोरियावी में श्री मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए बम विस्फोट में जान गंवाने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों के प्रति गहरी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कृत्य में शामिल लोगों को कठोर से कठोर से सजा दिलाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और इस लड़ाई में वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री का नाम शीर्ष पर है।

उन्होंने सागर सैनिक स्कूल के लोकार्पण अवसर पर कहा कि मोतीभाई चौधरी की सादगी और आदर्श जीवन सहकारी क्षेत्र के अग्रणियों के लिए मार्गदर्शक बना है, सहकारी क्षेत्र के ऐसे अनेकों अग्रणियों की मेहनत से आज देश और राज्य के किसानों, पशुपालकों और गांवों के लिए समृद्धि के द्वार खुल गए हैं।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के चलते आज सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर देश में 100 नए सैनिक स्कूलों का निर्माण हुआ है, जिससे राष्ट्र के बालक सेना में पहुंच रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने खेरालू में ऑर्गेनिक प्लांट के लोकार्पण अवसर पर कहा कि इस प्लांट से किसानों की आय में सुधार के साथ-साथ देश के नागरिकों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अमूल जैसे विश्वसनीय ब्रांड से वैश्विक स्तर पर इन उत्पादों की मांग होगी, जिससे प्राकृतिक-ऑर्गेनिक उत्पाद उगाने वाले किसान समृद्ध होंगे। उन्होंने किसानों से अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक उत्पादों का उपभोग करने की भी अपील की।

केंद्रीय मंत्री ने दूधसागर डेयरी के सहकारी मॉडल की बात करते हुए कहा कि 1960 में 3300 लीटर की क्षमता के साथ शुरू हुई यह डेयरी आज 35 लाख लीटर दूध का उत्पादन कर रही है। दस लाख उत्पादकों के साथ 8000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली इस डेयरी के माध्यम से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और राष्ट्र के विकास में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे रही हैं।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि दूध सागर डेयरी और बनास डेयरी अर्थव्यवस्था के बदलाव का सहकारी क्षेत्र का मॉडल हैं। उन्होंने राज्य के डेयरी मॉडल को समझने के लिए देश के 50 सांसदों द्वारा किए गए बनासकांठा के दौरे के बारे में भी चर्चा की।

उन्होंने देश में सहकारिता क्षेत्र में गढ़े गए अनेक नए आयामों के बारे में विस्तार से बताया और सहकारी क्षेत्र में गांवों को मजबूत बनाने के लिए की जा रही अनेक नई पहलों के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ने बेमौसम बारिश के चलते राज्य सरकार द्वारा घोषित पैकेज का स्वागत किया और इस उदार पैकेज की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की इस विकट परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़े रहकर और अभूतपूर्व पैकेज की घोषणा कर किसानों का आशीर्वाद प्राप्त किया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात में बेमौसम बारिश के कारण हुए नुकसान के मद्देनजर किसानों के साथ खड़े रहने के लिए डबल इंजन सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक राहत पैकेज घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इस सहायता से किसानों की सारी मुश्किलें दूर नहीं होंगी, लेकिन उन्हें सहारा अवश्य मिलेगा। ऐसी कठिन परिस्थिति में केंद्र और राज्य सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही हैं।

उन्होंने आगे समर्थन मूल्य पर खरीद की चर्चा करते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसी भी फसल की 25 फीसदी खरीदी की जा सकती है, लेकिन इस विषय में प्रधानमंत्री से गुहार लगाने के बाद किसानों को खरीदी में भी छूट दी गई है। इसके अंतर्गत स्टॉक की मंजूरी इस प्रकार दी गई है, ताकि प्रति किसान 125 मन मूंगफली की खरीदी की जा सके, इससे किसानों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सैन्य शक्ति का विश्व को परिचय दिया है। इस वर्ष राष्ट्र भावना की चेतना जगाने वाले अनेक उत्सव मनाए जा रहे हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, वंदे मातरम्@150, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी वर्ष, संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष सहित राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले उत्सवों को मनाए जाने के साथ दूधसागर डेयरी द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन भी राष्ट्र भावना उजागर करने वाली गौरवपूर्ण घड़ी है।

श्री पटेल ने जोड़ा कि प्रबल राष्ट्र भावना उत्तर गुजरात का स्वभाव रहा है। ऐसे में श्वेत क्रांति की ख्याति दिलाने वाले सहाकारिता अग्रणी एवं दूधसागर डेयरी के पूर्व अध्यक्ष श्री मोतीभाई चौधरी के नाम से कार्यरत हुआ यह सैनिक स्कूल राष्ट्रहित सर्वोपरि ध्येय के साथ भावी पीढ़ी के निर्माण का माध्यम बनेगा। मोतीभाई चौधरी के जन्म शताब्दी वर्ष में शिलान्यस्त हुए इस सैनिक स्कूल का अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में लोकार्पण होना भी शुभ संयोग है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में उसके सुरक्षा बलों की सैन्य सज्जता महत्वपूर्ण होती है। ऐसी सज्जता अनुशासन, देशभक्ति के भाव तथा स्कूली शिक्षा का समन्वय सैनिक स्कूल में होता है। देशभक्ति के रंग में रंगे ऐसे लगभग 100 सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाएगी। ऑर्गेनिक प्लांट के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के सशक्तिकरण की आज एक नई परियोजना जुड़ी है। सागर ऑर्गेनिक प्लांट-खेरालू के लोकार्पण से इस प्लांट में तैयार होने वाले ऑर्गेनिक अनाज, दाल, मसालों आदि उत्पादों की अमूल ब्रैंड तले बिक्री होने वाली है, जिसकी दैनिक 30 टन उत्पादन क्षमता है। ऑर्गेनिक प्लांट में तैयार होन वाले अनाज, दाल, मसाले स्वदेशी उत्पादों व उनके उपयोग को गति देंगे।

इस अवसर राज्य के सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आज सहकारिता विभाग विकास की नई ऊंचाइयां पार कर रहा है। साथ ही देश के प्रथम सहकारिता मंत्री के रूप में श्री शाह ने देश के सहकारिता क्षेत्र के ढांचे को मजबूत करने के लिए अनेक नए उपक्रम शुरू कराए हैं। देश के सहकारिता क्षेत्र में 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र को साकार करने वाले व्यापक परिणाम हम देख रहे हैं, जिसमें आज सैनिक स्कूल का लोकार्पण श्वेत क्रांति से राष्ट्र क्रांति की ओर पहल प्रेरणादायी है।

उन्होंने बेमौसम बारिश के चलते राज्य सरकार द्वारा सहायता पैकेज की घोषणा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐतिहासिक पैकेज के साथ ऐतिहासिक प्रस्ताव कर शुक्रवार से किसानों के फॉर्म भरने का कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे तीव्र गति से किसानों को सहायता मिलेगी। इसके लिए सरकार कटिबद्ध बनी है। उन्होंने कहा कि सहायता पैकेज में कोई किसान वंचित न रह जाए, इसकी चिंता सरकार द्वारा की गई है। इसके लिए शुक्रवार से ग्रामीण स्तर पर फॉर्म भरने का कार्य शुरू होगा और किसानों को तत्काल सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने श्री मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल का तकती अनावरण कर लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ सहज संवाद कर सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों के अभ्यास तथा स्कूल में कराई जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

इस कार्यक्रम में प्राकृतिक उत्पादन करने वाले किसानों तथा डेयरी के बीच महानुभावों के करकमलों से एमओयू किए गए। इसके अलावा, दूधसागर डेयरी के सहयोग से नवाचार से समृद्धि प्राप्त करने वालीं आशाबेन प्रजापति का सम्मान किया गया।

इस अवसर पर दूधसागर डेयरी के अध्यक्ष श्री अशोकभाई चौधरी ने स्वागत संबोधन करते हुए डेयरी की उपलब्धियों तथा सैनिक स्कूल व ऑर्गेनिक प्लांट के बारे में जानकारी दी। यहाँ उल्लेखनीय है कि दूधसागर डेयरी तथा दूधसागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन (दुरडा) द्वारा लगभग 20 बीघा भूमि में निर्मित ग्रीन फील्ड परिसर में मोतीभाई आर. चौधरी सैनिक स्कूल का निर्माण किया गया है। इसमें कक्षा 6 से 12 के 750 विद्यार्थियों के पढ़ने, रहने, खेल-कूद तथा अन्य गतिविधियों के लिए परिसर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, दूधसागर डेयरी मेहसाणा द्वारा नए सागर ऑर्गेनिक प्लांट-खेरालू का भी ई-लोकार्पण किया गया है। इस प्लांट में ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद किसानों से उचित मूल्य पर खरीद कर ग्राहकों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन 30 मैट्रिक टन प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग की व्यवस्था वाले आधुनिक प्लांट और छोटे उपभोक्ता उन्मुखी पैक तथा पैकिंग की व्यवस्था से युक्त प्लांट का निर्माण किया गया है।

इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी, ऊर्जा मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल, पूर्व मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तृषाबेन पटेल, सांसद सर्वश्री हरिभाई पटेल, भरतसिंह डाभी, मयंकभाई नायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नीतिनभाई पटेल, विधायक सर्वश्री मुकेशभाई पटेल, किरीटभाई पटेल, सरदार चौधरी, सुखाजी ठाकोर, राजेन्द्र चावडा, लविंगजी ठाकोर, पूर्व मंत्री श्री दिलीप ठाकोर, अग्रणी सर्वश्री गिरीशभाई राजगोर, वर्षाबेन दोशी, जिला कलेक्टर श्री एस. के. प्रजापति, जिला विकास अधिकारी श्री हसरत जैस्मीन, प्रबंध निदेशक श्री धीरजकुमार चौधरी, उपाध्यक्ष श्री योगेशभाई पटेल, दूधसागर डेयरी के निदेशक, सहकारिता क्षेत्र के अग्रणी सहित महानुभाव और किसान-पशुपालक उपस्थित रहे।

राजमार्गों तथा नगरों-महानगरों के सड़क मार्गों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किए जाएगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री तथा मुख्य सचिव की उपस्थिति में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए दिशानिर्देश

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं कि राज्य में राजमार्गों तथा नगरों-महानगरों में सड़क मार्ग कार्यों की गुणवत्ता से कम्प्रोमाइज या समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई तथा मुख्य सचिव श्री एम. के. दास की उपस्थिति में आयोजित बैठक में ये दिशानिर्देश दिए। बैठक में महानगरों के महापौर, महानगर पालिकाओं की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, महानगर पालिकाओं के आयुक्त तथा क्षेत्रीय महानगर पालिका आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और उन्होंने अपने नगरों-महानगरों की सड़क मार्गों की स्थिति का विवरण दिया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जब से शासन दायित्व संभाला है, तब से राज्य में सड़क मार्गों-पुलों के निर्माण में गुणवत्ता पर निरंतर बल दिया है।

ऐसे जन हित के कार्यों में क्वॉलिटी में कम्प्रोमाइज या समझौता करने की बात बर्दाश्त नहीं की जाती है। मुख्यमंत्री ने अनेक बार इसकी प्रतीति भी कराई है। हाल ही में 3 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है।

इतना ही नहीं; हल्की गुणवत्ता के कार्य करने वाले 13 से अधिक ठेकेदारों को इस वर्ष ब्लैक लिस्ट करने तक के कड़े दंडात्मक कदम भी मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश पर उठाए गए हैं।

श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार दोपहर को आयोजित इस बैठक मे स्पष्ट रूप से कहा कि सड़कों पर के पोटहोल्स भरने के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए। इतना ही नहीं; सम्बद्ध अधिकारी, मनपा आयुक्त व उपायुक्त नियमित रूप से फील्ड विजिट कर कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करते रहें और 30 नवंबर तक सड़क मार्गों की समग्र स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पुलों के कार्य हो रहे हों, वहाँ डाइवर्जन के लिए आरसीसी रोड बने, जिससे सम्बद्ध कार्य पूरा होने तक नागरिकों को परिवहन में कोई असुविधा न हो। इसके लिए भी उन्होंने बैठक में सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रभारी मंत्रियों को उनके जिलों में सड़कों की स्थिति की सम्बद्ध अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर 30 नवंबर तक स्थिति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।

श्री पटेल ने इस उच्च स्तरीय बैठक में यह भी कहा कि जो सड़क मार्ग मैंटेनेंस गारंटी पीरियड में टूट जाएँ, उनके ठेकेदारों को तत्काल ब्लैक लिस्ट करने सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इस बैठक में कहा कि शहरों में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मार्केट जैसे स्थलों, जहाँ लोगों की अधिक आवाजाही रहती हो, वहाँ शहरी प्रशासन तथा सड़क एवं भवन विभाग इस तरह सड़क मरम्मत के कार्य करे, जिसकी लोगों को अनुभूति हो। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क मरम्मत को लेकर मिलने वाली शिकायतों का त्वरित निरावण, साथ ही साथ अन्य मरम्मत एवं नए सड़क निर्माण कार्य भी होते रहना जरूरी हैं।

इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. थेन्नारसन, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, कमिशनर ऑफ म्युनिसिपालिटीज सुश्री रेम्या मोहन, सड़क एवं भवन विभाग के सचिव श्री प्रभात पटेलिया, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) श्री धीरज पारेख, सड़क एवं भवन तथा शहरी विकास विभाग के सम्बद्ध अधिकारी उपस्थित रहे

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं पश्चिम रेलवे के मध्य हुए समझौता ज्ञापन (MOU) के अंतर्गत तीन रेल कर्मचारियों के परिवार को को वित्तीय सहायता राशि का वितरण

(जीएनएस)। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पश्चिम रेलवे के मध्य हुए समझौता ज्ञापन (MOU) के अंतर्गत भावनगर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन बैंक की ओर से मृतक रेल कर्मचारियों के परिजनों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने उक्त समझौते की प्रमुख शर्तों, लाभों एवं बीमा सुरक्षा से संबंधित जानकारियाँ विस्तार से साझा कीं। यह पहल रेलवे कर्मचारियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मृतक कर्मचारी श्री नरेंद्रसिंह जे गोहिल, कार्यालय अधीक्षक, भावनगर टर्मिनस के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के द्वारा दिया गया । साथ ही, मंडल रेल प्रबंधक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा श्री नरेंद्र सिंह गोहिल के परिजनों को 1 करोड़ 15 लाख की राशि का चेक संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त श्री विपिनभाई मकवाना, कार्यालय अधीक्षक, भावनगर मंडल कार्यालय के परिजन को 10 लाख की राशि एवं श्री किशोरसिंह, कनिष्ठ अभियंता, भावनगर टर्मिनस के परिजन को 10 लाख की राशि Union Bank of India की ओर से प्रदान की गई।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने की। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा सहित सभी शाखा अधिकारी एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा जी ने अपने संबोधन में कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के रेलकर्मियों एवं उनके परिजनों के हित में की गई यह पहल न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि बैंक और रेलवे के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को भी और मजबूत करती है।"

कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ मंडल कार्मिकअधिकारी श्री हुबलाल जगन के मार्गदर्शन में किया गया एवं संचालन सहायक कार्मिक अधिकारी श्री वाई राधेश्याम द्वारा किया गया । अंत में बैंक एवं रेलवे के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित याहामोगी माता देवमोगरा धाम के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, जानिए मंदिर का पौराणिक इतिहास

देवमोगरा धाम में विराजमान हैं आदिजाति समाज की कुलदेवी पांडोरी माता, यहाँ आयोजित होता है नर्मदा जिले का सबसे बड़ा मेला

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 नवंबर को नर्मदा जिले में जनजातीय गौरव दिवस के राष्ट्रीय स्तर के समारोह में शामिल होंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर, 13 नवंबर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से इस वर्ष गुजरात सहित देशभर में आदिजाति समाज के जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भव्य रूप से मनाई जा रही है। आदिजाति समुदाय के पराक्रम, बलिदान एवं सांस्कृतिक विरासत को जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय किया था। इस वर्ष जनजातीय गौरव दिवस का राष्ट्रीय स्तर का उत्सव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुजरात में नर्मदा जिले के डेडियापाडा में आयोजित होगा। नर्मदा जिले की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री प्रसिद्ध याहामोगी देवमोगरा धाम में माताजी के दर्शन करेंगे। सतपुड़ा पर्वतमाला में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित यह मनमोहक धाम आदिजाति समाज के लोगों की आस्था का केन्द्र है, जिसकी महिमा अनूठी है।

सतपुड़ा की पर्वतमाला के बीच स्थित पौराणिक मंदिर देवमोगरा धाम बाहर से नेपाल के पशुपतिनाथ जैसा दिखाई देता है

नर्मदा जिले की सागबारा तहसील के देवमोगरा में आदिजातियों की कुलदेवी पांडोरी माता (याहमोगी) का मंदिर स्थित है। सतपुड़ा की पर्वतमालाओं में प्रकृति की गोद में बसे इस धाम में स्वयंभू याहा पांडोरी देवमोगरा माता आदि-अनादि काल से स्वयं कणी-कंसरी के रूप में विराजमान हैं। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के आदिजाति समुदाय के लोग याहामोगी पांडोरी की कुलदेवी के रूप में अपार श्रद्धा-आस्था तथा भक्ति के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। इस पवित्र हेला दाब की आदि-अनादि काल से बहुत अनूठी महिमा रही है। हजारों वर्ष पूर्व जब इस प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा था, तब माताजी ने देवमोगरा धाम पर स्वयं वास किया था। भीषण अकाल के कारण अन्न-जल की किल्लत पैदा हुई और पशु-पक्षी तथा मानव; सभी दुःखी हो गए। ऐसे संकट की घड़ी में इस क्षेत्र के प्रजापालक गोर्या कोठार ने आवश्यक अन्न का वितरण करना शुरू किया, परंतु आगे चलकर गोर्या कोठार के अन्न भंडार भी खाली होने लगे। तब उनकी पालक पुत्री याहा पांडोरी ने कणी-कंसरी का रूप धारण कर अन्न वितरण का कार्य संभाला। तब से आज तक अनाज के भंडार कभी खाली नहीं हुए हैं। अर्थात् आदि-अनादि काल से लेकर आज तक माताजी के अन्न भंडार समग्र मानव जाति के लिए सदैव भरे रहे हैं। सागबारा तहसील के देवमोगरा गाँव में स्थित इस मंदिर में अनेक पीढ़ियों से लाखों भक्त माताजी के चरणों में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अपनी समस्याओं तथा दुःखों का निवारण प्राप्त करने के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी द्वारा माताजी का आह्वान किया जाता है और आशीर्वाद देकर हर व्यक्ति के कल्याण की मंगलकामना की जाती है। माताजी के चरणों में जो भी दुःखी व्यक्ति रोता हुआ आता है, वह हँसता हुआ वापस लौटता है।

देवमोगरा धाम : आदिजाति समाज की आस्था, परंपरा तथा संस्कृति का जीवंत प्रतीक

आदिजाति समुदाय हजारों वर्षों से अपनी अनूठी परंपरा का पालन करता है, जिसमें वे संपूर्ण श्रद्धा के साथ नई फसल को बाँस की टोकरी में रखते हैं और सब्जी-भाजी, पूजा सामग्री की हिजारी (हिंगारी) बांधकर उसे सिर पर रखकर एवं रंगबिरंगी वस्त्र पहनकर तथा महिलाएँ सोने-चांदी के आभषणों से सज्ज होकर गाजे-बाजे के साथ होब यात्रा पर निकलते हैं। आदिवासी लोग सवा महीने का व्रत-उपवास कर याहा पांडोरी देवमोगरा के चरणों में धान-अन्न श्रद्धापूर्वक समर्पित करते हैं और इसके बाद नए धान का सेवन किया जाता है। इस प्रकार; देवमोगरा धाम केवल एक स्थानक ही नहीं है, बल्कि आदिजाति समाज की आस्था, परंपरा एवं संस्कृतिक का जीवंत प्रतीक है और स्थानीय प्रदेश के घेरिया (महिला पोशाक में पुरुषों की टोली) होली-धुलंडी के त्योहार के दौरान सवा महीने घर से बाहर निकल कर घर-घर घूमते हैं और घेरिया बनते हैं और नौ रस के श्रृंगार के साथ मुक्त मन से नाच-गान करते हैं। धुलंडी से पूर्व के दिन होली चौक में होलिका प्रज्ज्वलित की जाती है और महिलाएँ भी परंपरागत वेशभूषा में सज्ज होकर कर वाद्ययंत्रों के साथ नाच-गान करते हुए होली के लोले (लोक गीत) गाकर आनंद-उत्सव मनाती हैं।

आदिवासी लोक संस्कृति का अनूठा दर्शन कराता है महाशिवरात्रि का मेला

देवमोगरा में जहाँ राजा पांठा-विनादेव का स्थानक है, वहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि पर एक भव्य गढ़ यात्रा आयोजित की जाती है। इस यात्रा में परंपरागत वाद्ययंत्रों तथा नृत्य के साथ माताजी को गढ़ में जंगलों-पर्वतों के बीच स्थित प्राकृतिक झरने में स्नान कराया जाता है। इतना ही नहीं; माताजी की पूजा करके आगामी वर्ष के लिए खेतीबाड़ी और बरसाती मौसम का (होलको ठोक कर) अनुमान लगाया जाता है। हजारों श्रद्धालु इस अनुमान के अनुसार खेतीबाड़ी का पूर्व आयोजन करते हैं। मेले के दौरान माता के प्रांगण में स्थित काकड़ के पेड़ पर एक ही रात में फूल आ जाते हैं। सुबह भक्त उसके दर्शन करते हैं और मानते हैं कि जिस दिशा में सबसे ज्यादा फूल हों, उस दिशा में वर्ष के दौरान खेतीबाड़ी का काम अच्छा होगा। प्रतिवर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तथा महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व से लगातार पाँच दिनों तक लगने वाला यह मेला आदिवासी लोक संस्कृति का अनूठा दर्शन कराता है। इस मेले में लाखों भक्त माताजी के दर्शन के लिए जुटते हैं, जो वास्तव में आह्लादक दृश्य होता है। इस मंदिर में बाईं ओर श्यामवर्णी महाकाली माता की मूर्ति के भी लोग दर्शन करते हैं। इस प्रकार; एक ही मंदिर में दो माताजी विराजमान हैं।

देश को मिलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल, गुजरात से अमित शाह ने दी ऐतिहासिक घोषणा

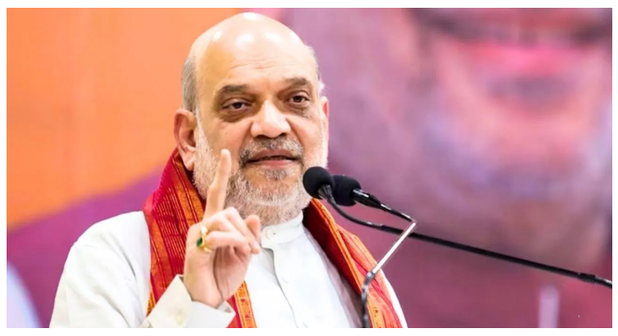

(जीएनएस)। गुजरात के मेहसाणा जिले में गुरुवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के युवाओं के भविष्य को बदलने वाली एक बेहद अहम घोषणा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक–निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत पूरे देश में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भारत में सैन्य शिक्षा के स्तर और रक्षा तैयारियों में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। शाह ने बताया कि इन स्कूलों का उद्देश्य न केवल बच्चों को सैन्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित करना है, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना को बचपन से ही विकसित करना भी है।

इस अवसर पर श्री मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने कहा कि मेहसाणा में तैयार किया गया मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल स्थानीय बच्चों और पूरे उत्तर गुजरात के लिए गौरव का प्रतीक बनेगा। इस स्कूल का निर्माण लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और यह अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यहां स्मार्ट क्लासरूम, विशाल छात्रावास, सुव्यवस्थित पुस्तकालय और साफ–सुथरी आधुनिक कैंटीन जैसी व्यवस्थाएँ तैयार की गई हैं। शाह ने कहा कि इस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं विद्यार्थियों को सैन्य करियर की ओर प्रेरित करेंगी और देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले युवा यहां से तैयार होंगे।

अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने सागर ऑर्गेनिक प्लांट के महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि अमूल ब्रांड के तहत देशभर में विश्वसनीय जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह संयंत्र किसानों के लिए नए युग की शुरुआत करेगा। इस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 30 मीट्रिक टन जैविक उत्पादों को प्रोसेस करने की क्षमता है और इसे राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम तथा एपीईडीए से प्रमाणित किया गया है। शाह ने कहा कि इन प्रमाणनों के कारण उत्तरी गुजरात में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की उपज अब विश्व बाजार तक पहुँच सकेगी। इससे उन्हें बेहतर कीमत मिलेगी और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जैविक खेती से तैयार उत्पाद देश की जनता के स्वास्थ्य सुधार में अहम भूमिका निभाएंगे।

अमित शाह ने अपने भाषण में दूधसागर डेयरी की ऐतिहासिक यात्रा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्ष 1960 में मात्र 3,300 लीटर प्रतिदिन दूध एकत्र करने वाली यह डेयरी आज 35 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता तक पहुंच चुकी है। यह उपलब्धि गुजरात के 1,250 गांवों और राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 10 लाख से अधिक दूध उत्पादक समूहों की मेहनत का परिणाम है। शाह ने कहा कि डेयरी का कारोबार आज 8,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गया है और यह गुजरात की श्वेत क्रांति में प्रमुख भूमिका निभा रही है। दूधसागर डेयरी में वर्तमान समय में आठ आधुनिक डेयरियां, दो दूध शीतलन केंद्र, दो चारा संयंत्र और एक सीमेंट उत्पादन इकाई भी संचालित हो रही हैं, जो इसकी चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं।

शाह ने बताया कि अमूल के कुल कारोबार का लगभग 70 प्रतिशत योगदान देशभर की ग्रामीण महिलाओं का है, जो यह सिद्ध करता है कि किस प्रकार डेयरी सहकारिता ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 75,000 नई प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका मिलेगी और पशुपालन क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी।

अपने संबोधन के दौरान शाह ने गुजरात में इस साल हुई बेमौसम भारी बारिश का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रभावित किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने उदार राहत पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार किसानों की सहायता करने के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगी और हर किसान के कठिन समय में सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी।

अंबाजी का मार्बल बना विश्व पहचान का प्रतीक, जीआई टैग मिलने से चमका बनासकांठा का गौरव

(जीएनएस)। गुजरात के बनासकांठा जिले का पवित्र तीर्थ अंबाजी सदियों से आस्था, अध्यात्म और शक्ति की भूमि के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन अब यह वही अंबाजी अपनी धरती की गोद से निकलते एक अनमोल खजाने की वजह से विश्व मानचित्र पर नई तरह से उजागर हो गया है। अंबाजी के प्रसिद्ध दूधिया सफेद मार्बल को भारत सरकार द्वारा "भौगोलिक संकेत" यानी जीआई टैग की मान्यता मिल गई है, जिसके साथ ही यह पत्थर न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी अलग और कानूनी पहचान के साथ चमकने लगा है। यह उपलब्धि न केवल पत्थर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि संपूर्ण बनासकांठा जिले के लिए गौरव और आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय भी है। राज्य सूचना विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, अंबाजी के मार्बल को यह मान्यता अनेक महीनों की तकनीकी जांच, दस्तावेजी अध्ययन और क्षेत्रीय विशिष्टताओं के मूल्यांकन के बाद प्रदान की गई। अंबाजी मार्बल क्वॉरी एंड फैक्ट्री एसोसिएशन की ओर से किए गए पंजीकरण के साथ-साथ स्टोन आर्टिसन पार्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सप्ती), कमिश्नर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग और जिला प्रशासन ने मिलकर इस प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सहयोग इस बात का प्रतीक है कि जब परंपरा, तकनीक, प्रशासन और उद्योग साथ खड़े हों, तो क्षेत्रीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय पहचान तक पहुँच सकते हैं।

नई दिल्ली में आयोजित उद्योग मंत्रालय के कार्यक्रम में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बनासकांठा के भू-वैज्ञानिक गुरप्रीत सिंह को जीआई टैग का प्रमाणपत्र सौंपकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों और अधिकारियों ने कहा कि अंबाजी मार्बल की गुणवत्ता, उसकी चमक और प्राकृतिक मजबूती उसे दुनिया के उच्च गुणवत्ता वाले मार्बल की श्रेणी में खड़ा करती है और जीआई टैग मिलने के बाद इसके बाजार मूल्य और निर्यात संभावनाओं में बड़ी वृद्धि होगी। बनासकांठा के जिला कलेक्टर मिहिर पटेल ने इस उपलब्धि को अंबाजी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शक्ति पीठ के रूप में अंबाजी मंदिर को विश्वभर के श्रद्धालुओं का सम्मान मिला है, उसी तरह अब अंबाजी से निकलने वाला मार्बल भी गुजरात की धरती की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अंबाजी अब श्रद्धा का केंद्र होने के साथ ही प्राकृतिक संपदा, स्थानीय कला कौशल और औद्योगिक प्रगति का संगम बन चुका है।

अंबाजी का यह मार्बल अपनी दूधिया सफेदी, प्राकृतिक चमक और दीर्घायु के कारण सदियों से प्रसिद्ध रहा है। अंबाजी मंदिर के गर्भगृह और आसपास के कई विशालकाय निर्माणों में इसी पत्थर का उपयोग किया गया है, जो आज भी उसी तेजस्विता के साथ चमकता है। स्थानीय कारीगरों की परंपरागत तकनीक और हाथों की महीन कलाकारी इस पत्थर को केवल एक निर्माण सामग्री नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत बना देती है। कई धार्मिक स्थलों, स्मारकों और भव्य इमारतों में अंबाजी मार्बल का इस्तेमाल इसकी गुणवत्ता और पवित्रता के कारण किया जाता है।

जीआई टैग किसी उत्पाद को सिर्फ एक पहचान नहीं देता, बल्कि उसे एक कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि अब अंबाजी नाम का उपयोग केवल वही मार्बल कर सकेगा, जो वास्तव में अंबाजी क्षेत्र से निकला हो। इससे न केवल नकली उत्पादों पर रोक लगेगी, बल्कि स्थानीय खनिकों, कारीगरों और उद्योगों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। जीआई टैग मिलने के बाद अंबाजी मार्बल की कीमत, वैश्विक मांग और निर्यात में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है।

भारत में जीआई टैग उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत चेन्नई स्थित कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह प्रमाणपत्र उन उत्पादों को मिलता है, जिनकी गुणवत्ता और विशिष्टता पूरी तरह उनके मूल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, मिट्टी, जलवायु या पारंपरिक कारीगरी से जुड़ी होती है। अंबाजी मार्बल इस श्रेणी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपने क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं और स्थानीय कारीगरों की पीढ़ियों पुरानी कला पर आधारित है।

जीआई टैग मिलने के साथ अंबाजी अब केवल एक धार्मिक धाम नहीं रहा, बल्कि उद्योग, कला और परंपरा का अद्भुत संगम बनकर उभर रहा है। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब भारत अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक ब्रैंड में बदलने की दिशा में अग्रसर है। आने वाले वर्षों में अंबाजी मार्बल न केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी चमक दिखाएगा, बल्कि बनासकांठा के हजारों परिवारों के जीवन में भी नई रोशनी लाएगा।

भारत–नेपाल ने रेल व्यापार सहयोग को दी नई रफ्तार, पारगमन संधि में संशोधन से माल ढुलाई और सुगम

(जीएनएस)। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। नई दिल्ली में आयोजित द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने रेल-आधारित व्यापार संपर्क बढ़ाने पर सहमति जताई और पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन से जुड़े दस्तावेजों का आदान–प्रदान किया। इस समझौते को दोनों देशों के बीच व्यापारिक आवागमन की गति बढ़ाने वाला और नेपाल के अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नेपाल के उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री अनिल कुमार सिन्हा की उपस्थिति में हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत रेल मार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को और बेहतर, सुरक्षित और तेज बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह संशोधन भारत–नेपाल के बीच जोगबनी (भारत) से विराटनगर (नेपाल) तक माल परिवहन को अत्यंत सरल बनाएगा। इसके साथ ही यह व्यवस्था कोलकाता–जोगबनी, कोलकाता–नौतनवा (सुनौली) और विशाखापत्तनम–नौतनवा जैसे प्रमुख पारगमन गलियारों तक विस्तारित होगी, जिससे नेपाल के व्यापार को विशेष रूप से लाभ मिलेगा।

नेपाल, जो समुद्र से घिरा हुआ देश नहीं है, अपने आयात–निर्यात के लिए भारत के बंदरगाहों और पारगमन व्यवस्था पर निर्भर रहता है। ऐसे में रेल-आधारित परिवहन न केवल परिवहन लागत कम करेगा बल्कि समय की भी बचत करेगा। इस सुधार से संबंधित मंत्रालयों का मानना है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक सुगमता अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ेगी और सीमा पार माल ढुलाई में आने वाली कई बाधाएँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच यह सहयोग दोनों देशों के साझा आर्थिक हितों के अनुरूप है और इससे बहु-विधीय व्यापार संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेल व्यापार संपर्कों के विस्तार के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी अधिक गहरी और व्यापक होगी। गोयल के अनुसार, यह कदम न केवल द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाएगा, बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने में सहायता करेगा।

नेपाल के उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक सहयोग का नया अध्याय है। सिन्हा ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच पारगमन संधि में किया गया यह संशोधन न केवल व्यापार को गति देगा, बल्कि नेपाल के लिए तीसरे देशों के साथ वाणिज्यिक संपर्क मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे सीमा पर परिवहन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, सहज और तेज़ बनेगी, जो भविष्य में आर्थिक विकास की गति को कई गुना बढ़ाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत–नेपाल व्यापार सहयोग में यह सुधार ऐसे समय पर आया है, जब दोनों देशों के बीच बहुक्षेत्रीय साझेदारी लगातार विस्तारित हो रही है। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, जल प्रबंधन और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों के साथ अब व्यापारिक पारगमन और रसद प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभर रहा है। इस समझौते से नेपाल को भारत के विस्तृत रेल नेटवर्क का लाभ मिलेगा और सीमाई क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियाँ और तेज होंगी।

यह नया समझौता क्षेत्रीय व्यापार के लिए भी अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और नेपाल की घनिष्ठ आर्थिक साझेदारी दक्षिण एशिया के व्यापारिक ढाँचे को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है।

नोएडा में दो युवाओं की आत्महत्या से सनसनी

(जीएनएस)। नोएडा में बुधवार का दिन बेहद दुखद साबित हुआ, जब गौतमबुद्ध नगर जिले में दो अलग-अलग आत्महत्या की घटनाओं ने शहर को स्तब्ध कर दिया। एक ओर एक निजी कंपनी में कार्यरत 40 वर्षीय कर्मचारी ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया, वहीं दूसरी ओर गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय का 20 वर्षीय छात्र हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे बैठा। दोनों घटनाओं ने परिवारों, दोस्तों और स्थानीय लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के पीछे के कारणों की तलाश की जा रही है। पहली घटना थाना बिसरख क्षेत्र की जेएम फ्लोरेंस सोसाइटी की है, जहां निवास करने वाले 40 वर्षीय दिवाकर सिंह ने अपने फ्लैट में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार दिवाकर हरियाणा की एक कंपनी में कार्यरत थे, जबकि उनकी पत्नी भी नौकरी करती हैं। घटना के समय पत्नी ड्यूटी पर थीं और दिवाकर घर में अकेले थे। देर शाम जब पत्नी घर लौटीं तो उन्होंने अपने पति को पंखे से लटका हुआ पाया और घबराकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुँची और शव को नीचे उतवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसके चलते आत्महत्या के कारणों को लेकर जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और परिवार से भी बातचीत की गई है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि दिवाकर किसी मानसिक तनाव या आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे या नहीं। दूसरी घटना थाना ईकोटेक-1 क्षेत्र की रामशरणदास हॉस्टल की है, जहां गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में बीए की पढ़ाई कर रहे 20 वर्षीय छात्र धीरज तिवारी ने हॉस्टल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

अमेरिका की सख्त कार्रवाई: ईरान के मिसाइल व ड्रोन नेटवर्क पर प्रहार भारत समेत आठ देशों के 32 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध

(जीएनएस)। वाशिंगटन। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान के सैन्य विस्तार को रोकने के प्रयास में अमेरिका ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की घोषणा की। वॉशिंगटन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन उत्पादन कार्यक्रम में सहयोग देने वाले एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को निशाने पर लेते हुए भारत समेत आठ देशों के 32 व्यक्तियों और संस्थाओं पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। यह कदम अमेरिकी प्रशासन की उस दीर्घकालिक नीति का हिस्सा है जिसके तहत वह तेहरान पर अधिकतम दबाव बनाकर उसके सैन्य कार्यक्रमों को सीमित करना चाहता है।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, जिन देशों से जुड़े व्यक्ति और संस्थाएं इस कार्रवाई की जद में आई हैं, उनमें ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्किये, चीन, हांगकांग, भारत, जर्मनी और यूक्रेन शामिल हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये सभी एक जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो ईरान को मिसाइल और ड्रोन निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी घटक, नेविगेशन सिस्टम, प्रिसिशन सेंसर, माइक्रोप्रोसेसर और रक्षा-ग्रेड सामग्रियां उपलब्ध कराते थे।

अमेरिकी खजाना विभाग के विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) की प्रमुख एंड्रिया गक्की ने बयान में कहा, "ईरान लगातार ऐसे हथियार बना रहा है जो न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की स्थिरता को चुनौती देते हैं। हमारी कार्रवाई यह स्पष्ट संदेश देती है कि जो भी देश, व्यक्ति या कंपनी इस नेटवर्क को सहयोग देगा, उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।"

बयान में कहा गया है कि यह नेटवर्क न केवल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए बल्कि लाल सागर, अरब सागर और भूमध्यसागर में चल रही वाणिज्यिक नौवहन गतिविधियों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा था। अमेरिका ने हाल के महीनों में बार-बार आरोप लगाया है कि ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों ने यमन और

सीरिया से कई ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें अमेरिकी और सहयोगी देशों के ठिकाने निशाना बने हैं।

इन प्रतिबंधों के तहत सभी संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की अमेरिकी परिसंपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और अमेरिकी नागरिकों व कंपनियों को उनसे किसी भी प्रकार के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन भारतीय संस्थाओं का नाम सूची में शामिल है, उनके बारे में अमेरिकी अधिकारियों ने फिलहाल विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह संकेत अवश्य दिया गया है कि इनमें से कुछ भारतीय व्यापारी और टेक्नोलॉजी आपूर्तिकर्ता ईरान से जुड़े मध्यस्थों के माध्यम से संवेदनशील सामग्रियों की आपूर्ति कर रहे थे।

वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुँचेगा और जो भी कंपनियां या व्यक्ति इस गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाए जाएंगे, उन पर भविष्य में और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

इस कार्रवाई को अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ पश्चिम एशिया में ईरान की बढ़ती सैन्य उपस्थिति को नियंत्रित करने के व्यापक प्रयास के रूप में देख रहे हैं। पिछले एक वर्ष में ईरान ने कई बार यह दावा किया है कि उसने स्वदेशी तकनीक से विकसित ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इन मिसाइलों की रेंज 2,000 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है, जो इज़राइल सहित कई अमेरिकी ठिकानों तक पहुँच सकती है।

अमेरिका और यूरोपीय देशों का मानना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की आड़ में हथियार उत्पादन क्षमता को गुप्त रूप से बढ़ा रहा है। वहीं, तेहरान ने इन आरोपों को "राजनीतिक साजिश" बताते हुए सिरे से खारिज किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए है। तेहरान ने अमेरिका की इस कार्रवाई को "दबाव की राजनीति" बताते हुए कहा कि इससे न तो उसके वैज्ञानिक प्रयास रुकेंगे, न ही वह पश्चिमी देशों के आगे झुकेगा।

विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम अमेरिका की ओर से सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश है कि जो भी देश या निजी संस्था आतंकवाद, हथियारों के प्रसार या अस्थिरकारी सैन्य गठबंधनों को समर्थन देगा, उसे वैश्विक आर्थिक तंत्र से बाहर कर दिया जाएगा। भारत के लिए यह स्थिति संवेदनशील है, क्योंकि नई दिल्ली ईरान के साथ ऊर्जा, बंदरगाह विकास और क्षेत्रीय सहयोग के कई प्रोजेक्ट चला रही है। ऐसे में अमेरिका की यह कार्रवाई भविष्य में कूटनीतिक और आर्थिक समीकरणों को जटिल बना सकती है।

पुणे में नवले पुल पर दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने मचाई तबाही, 8 की मौत, कई घायल

(जीएनएस)। पुणे। महाराष्ट्र के पुणे शहर में गुरुवार की शाम एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे शहर को हिला दिया। पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर स्थित नवले पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और करीब एक किलोमीटर के दायरे में 15 से 20 वाहनों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और कई वाहनों में आग लगने से पूरा इलाका धुएं और चीख-पुकार से भर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह ट्रक राजस्थान नंबर का था और सतारा से मुंबई की दिशा में जा रहा था। अचानक ब्रेक फेल हो जाने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्रक ने सामने चल रही कारों, दो ट्रकों और कई बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। एक के बाद एक टक्करों की आवाज़ से लोग दहशत में आ गए। हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई वाहन ट्रक के नीचे आकर पूरी तरह कुचल गए, जबकि एक कार में आग लगने से उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने किसी तरह फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कई वाहन आग की लपटों में घिर चुके थे। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल, पुलिस और एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घायल यात्रियों को पास के ससून अस्पताल और भारती अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर पहुंचे पुणे के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ट्रक के ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि "यह हादसा बेहद दर्दनाक है। मृतकों की पहचान की जा रही है और उनके परिजनों को सूचना भेजी जा रही है।"

नवले पुल के पास यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हादसा हुआ हो। इससे पहले भी इसी ढलान पर कई बार बेकाबू ट्रक और भारी वाहनों की वजह से बड़े हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की ढलान और खराब सिग्नलिंग सिस्टम के कारण यहां हादसों की संभावना हमेशा बनी रहती है। लोग लंबे समय से इस मार्ग पर ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

इस हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और पुलिस को यातायात को डायवर्ट करना पड़ा। रात भर बचाव और सफाई अभियान जारी रहा। हादसे के बाद से स्थानीय प्रशासन पर फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस ब्लैक स्पॉट को लेकर लगातार चेतावनियों के बावजूद कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कई घायल यात्रियों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। पुणे का यह हादसा एक बार फिर इस सच्चाई को सामने लाता है कि भारत में सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों के तकनीकी निरीक्षण में लापरवाही किस तरह सैकड़ों जिंदगियां हर साल निगल रही है।

जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौड़ मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार, ईडी ने बताया—खरीदारों की रकम से हुआ हेरफेर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को धनशोधन के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई है जब हजारों घर खरीदार अपने फ्लैटों की डिलीवरी को लेकर वर्षों से परेशान हैं। ईडी ने गौड़ को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया है। एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए खरीदारों से वसूली गई रकम को निर्माण कार्य में लगाने के बजाय अन्य कारोबारों में मोड़ दिया, जिससे न केवल परियोजनाएं रुकीं बल्कि निवेशकों को भारी नुकसान भी हुआ।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने यह गिरफ्तारी कई महीनों की जांच और वित्तीय लेनदेन की गहन पड़ताल के बाद की है। एजेंसी का कहना है कि यह मामला रियल एस्टेट सेक्टर में

निवेशकों की पूंजी के गलत उपयोग का एक बड़ा उदाहरण है। गौड़ से पूछताछ के दौरान ईडी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि खरीदारों से जुटाई गई हजारों करोड़ की रकम किन रास्तों से होकर अन्य कंपनियों या खातों में पहुंची।

गौरतलब है कि इसी साल मई में ईडी ने जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और उनसे जुड़ी कई सहायक कंपनियों के करीब 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इन छापों में एजेंसी को 1.7 करोड़ रुपये नकद, जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज, करोड़ों के वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा बरामद हुए थे। यही दस्तावेज आगे चलकर जांच की रीढ़ साबित हुए।

एजेंसी की प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कंपनी ने घर खरीदारों और बैंकों से प्राप्त राशि को वास्तविक निर्माण गतिविधियों के बजाय अपने अन्य प्रोजेक्ट्स और कारोबारी विस्तार में लगा दिया। इसके कारण न केवल घरों की डिलीवरी वर्षों तक अटकी रही, बल्कि हजारों खरीदारों को दोहरी मार झेलनी पड़ी—एक तरफ मकान न मिला और दूसरी तरफ लोन का ब्याज बढ़ता चला गया।

ईडी के अधिकारियों का कहना है कि जांच के अगले चरण में उन व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की जाएगी जिन्होंने इन अवैध फंडों को स्वीकार किया या छिपाने में मदद की। मनोज गौड़ से इस बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है, और संभावना है कि जल्द ही कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों या संबंधित कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।

जेपी इंफ्राटेक का मामला लंबे समय से विवादों में रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी कंपनी के रेज़ोल्यूशन प्लान पर कई बार पुनर्विचार हुआ, लेकिन खरीदारों की परेशानियां पूरी तरह खत्म नहीं हो पाईं। अब ईडी की यह कार्रवाई उन निवेशकों के लिए एक उम्मीद बनकर आई है जो सालों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

ईडी का मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरह की वित्तीय अनियमितताएं व्यापक स्तर पर हैं, और मनोज गौड़ की गिरफ्तारी भविष्य में अन्य बिल्डरों और डेवलपर्स के लिए भी एक कड़ा संदेश देगी कि खरीदारों की मेहनत की कमाई से किसी भी तरह का वित्तीय खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।